मुख्य समाचार :–

- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बजट–पूर्व संवाद कार्यक्रम में राज्य के विकास, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था और जनभागीदारी पर जोर दिया।
- पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने कहा–सरकार का लक्ष्य 2030 तक 1,953 पंचायत भवनों का निर्माण किया जाएगा।
- महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा–महिला सशक्तिकरण का अर्थ निर्णय–निर्माण और शासन के प्रत्येक स्तर पर महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित करना है।
- और.. "जन–जन की सरकार, जन–जन के द्वार" अभियान के तहत अब तक राज्य 5 सौ 89 आयोजित शिविरों में 4 लाख से अधिक नागरिकों ने प्रतिभाग किया।

बजट–पूर्व संवाद कार्यक्रम

उत्तराखंड के चंपावत जिले के बनबसा एनएचपीसी सभागार, बनबसा में आयोजित बजट–पूर्व संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विकास, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था और जनभागीदारी पर जोर दिया।

इस अवसर पर सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने राज्य की आर्थिक प्रगति पर प्रकाश डालते हुए बताया कि पिछले पाँच वर्षों में प्रदेश के कैपिटल आउटले में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और यह राशि 7,534 करोड़ से बढ़कर 14,765 करोड़ रूपये तक पहुँच गई है। इसी अवधि में राज्य की जीडीपी बढ़कर 4,74,000 करोड़ रूपये हो गई है, जो लगभग 60 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाती है।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक गाँव में पिंक टॉयलेट जैसी सुविधाओं की दिशा में कार्य करेगी। उन्होंने वर्ष 2047 तक उत्तराखण्ड को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि छोटा राज्य होने के बावजूद राज्य ने वित्तीय प्रबंधन में देशभर में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है, जो गर्व का विषय है। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से आए जनप्रतिनिधियों, विभागीय अधिकारियों, विशेषज्ञों तथा हितधारकों ने अपने सुझाव प्रस्तुत किए।

विंटर कार्निवल

उधमसिंह नगर जिले में स्थित हेमवंती नंदन बहुगुणा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खटीमा में छात्र संघ द्वारा पहली बार विंटर कार्निवल के अंतर्गत भजन क्लम्बिंग जैसे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन किया गया। जिसमें प्रतिभाग करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस प्रकार की पहल केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि हमारी सनातन संस्कृति, लोक परंपराओं और युवा चेतना के संगम का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का आयोजन ये सिद्ध करते हैं कि देश का युवा वर्ग आधुनिकता के साथ अपनी जड़ों से भी मजबूती से जुड़ा हुआ है। श्री धामी ने विश्वास व्यक्त किया कि जिन छात्र–छात्राओं ने इस कार्यक्रम का संचालन किया है, वही कल राज्य और देश का नेतृत्व करेंगे।

समारोह

इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उधमसिंहनगर जिले के बिरिया मझोला खटीमा में स्वर्गीय मनीष चंद स्मृति द्वितीय ग्रामीण क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के समापन और पुरुस्कार वितरण समारोह में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि खिलाड़ी लक्ष्य लेकर संकल्प के साथ आगे बढ़ें सिद्धि तक अवश्य पहुंचेंगे। उन्होंने

कहा अब खेल एक मनोरंजन का साधन नहीं है, खेलो में कैरियर की अपार संभावनाएं हैं इसलिए लक्ष्य निर्धारित करते हुए अनुशासन के साथ खेले।

सरस कॉर्बेट महोत्सव

वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एनएचपीसी सभागार बनबसा में चम्पावत सरस कॉर्बेट महोत्सव के आधिकारिक टीज़र लॉन्च किया।

उन्होंने कहा कि महोत्सव चम्पावत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, धार्मिक आस्था, प्राकृतिक सौंदर्य और साहसिक पर्यटन गतिविधियों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने का माध्यम बनेगा।

उन्होंने कहा कि देवभूमि के सांस्कृतिक रंग, लोक परंपराएँ और प्रकृति की अद्भुत छटा इस आयोजन के माध्यम से देश–विदेश तक पहुँचेगी।

महोत्सव में कुमाऊँ की लोकसंस्कृति की जीवंत झलक दिखने के साथ ही जिले के प्रमुख आस्था केंद्र बालेश्वर मंदिर, पूर्णागिरि मंदिर और गोल्ज्यू देवता मंदिर आध्यात्मिक गरिमा महोत्सव की पहचान बनेंगे।

महोत्सव का आयोजन 18 से 24 फरवरी तक जिले में आयोजित होगा। महोत्सव का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्तराखंड में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने की दूरदर्शी परिकल्पना को साकार रूप देते हुए किया जा रहा है।

सतपाल महाराज

पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि प्रदेश में पंचायत की भूमि पर कहीं पर भी अतिक्रमण पाए जाने पर उसे तुरंत हटाए जाने पर जोर दिया। उन्होंने लैंड बैंक की स्थिति का आंकलन करने और 73वें संविधान संशोधन के तहत संविधान की 11वीं अनुसूची में वर्णित 29 विषयों को त्रिस्तरीय पंचायतों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया को तुरंत लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2030 तक 1,953 पंचायत भवनों का निर्माण करने को लेकर तैयारियां चल रही हैं।

उन्होंने ये निर्देश सहस्त्रधारा रोड, डंडा लखौंड स्थित पंचायतीराज निदेशालय में विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान दिए। उन्होंने 15वें वित्त आयोग द्वारा प्राप्त धनराशि की स्थिति साझा करते हुए बताया कि 2020–21 से 2025–26 तक राज्य को टाइट फंड से 1,182.6 करोड़ और अनटाइड फंड से 1,630.4 करोड़, कुल 2,813 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। इस धनराशि से पंचायतों में कंपोस्ट पिट, वर्मी कंपोस्ट पिट, कम्युनिटी डस्टबिन, कूड़ा संग्रहण वाहन, यात्री प्रतीक्षालय, रीसाइकलिंग प्लांट, प्लास्टिक वेस्ट प्रबंधन केंद्र, प्राथमिक कूड़ा संग्रहण केंद्र और कुल 1,362 पंचायत भवनों का निर्माण किया गया है।

कार्यशाला

महिलाओं को अंतरिक्ष तकनीक, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस एवं ड्रोन तकनीक जैसी आधुनिक तकनीक से जोड़ कर उन्हे शैक्षणिक एवं व्यावसायिक रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाना सरकार का लक्ष्य। इस उद्देश्य से देहरादून स्थित उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र–यूसैक के सभागार में महिला सशक्तिकरण विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला मे यूसैक के निदेशक एवं महानिदेशक यौकॉस्ट– प्रोव दुर्गेश पंत ने कहा कि वर्तमान समय में आधुनिक तकनीक के माध्यम से महिलाओं के लिए रोजागर, नवाचार, कौशल विकास व नेतृत्व के नए अवसर सृजित किए जा रहे हैं। आधुनिक युग में तकनीक ने समाज के हर क्षेत्र को प्रभावित किया है, विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में तकनीक से मजबूत माध्यम बन कर उभरी है। सूचना संचार प्रोधोगिकी,

इंटरनेट, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म,और सोशल मीडिया ने महिलाओं को नई पहचान, अवसर और आत्मनिर्भरता प्रदान की है। साथ ही एआई आधारित प्लेटफ़ॉर्म महिलाओं को रोजगार और कौशल विकास के नए अवसर प्रदान कर रहे हैं।

इस अवसर पर उत्तराखंड राज्य महिला आयोग कि अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा कि, महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को निर्णय निर्माण, नेतृत्व और शासन के हर स्तर पर समान अवसर, अधिकार और संसाधन उपलब्ध कराना।

जन–जन की सरकार, जन–जन के द्वार

प्रदेश में संचालित "जन–जन की सरकार, जन–जन के द्वार" अभियान राज्य में सुशासन, पारदर्शिता और त्वरित सेवा वितरण का प्रभावी उदाहरण बनकर उभरा है। इस अभिनव अभियान के माध्यम से सरकार स्वयं जनता के द्वार तक जाकर उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित कर रही है।

इस अभियान के अंतर्गत प्रदेश के सभी जिलों में नियमित रूप से आयोजित किये जा रहे जनसेवा शिविरों में आमजन को प्रशासनिक सेवाएं, शिकायत निवारण, प्रमाण पत्र तथा विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जा रहा है। गौरतलब है कि अब तक प्रदेश भर में कुल 5 सौ 89 शिविर आयोजित किये गए हैं, जिनमें से 8 शिविर कल आयोजित किये गये। इनमें अब तक कुल 4 लाख 63 हजार 9 सौ 56 नागरिकों ने प्रतिभाग किया।

अभियान में अब तक 45 हजार छह सौ एक प्राप्त शिकायतों में से 30 हजार सात सौ 23 का सफलतापूर्वक निस्तारण किया जा चुका है। यह आंकड़े सरकार की संवेदनशीलता और जवाबदेही को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। इस दौरान विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्रों के लिए नागरिकों से अब तक कुल 65 हजार 5 सौ 28 प्रमाण पत्रों के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिससे आमजन को कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। साथ ही विभिन्न राज्य एवं केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से अब तक 2,58,056 नागरिकों को लाभान्वित किया जा चुका है, जिससे समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित हुआ है।

अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर...

देहरादून दौरे पर रहें केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के हवाले से हिन्दुस्तान समाचार पत्र लिखता है– अब पर्वतीय शहरों को संवारेंगे, हिमालय राज्यों के लिए अलग शहर विकास नीति बनाएगी केंद्र सरकार।

ड्यूटी के लिए बजट नहीं, यातायात और थानों से हटाए गए 2 हजार 900 पीआरडी जवान– अमर उजाला इस शीर्षक के साथ खबर में लिखता है– निदेशालय युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल ने जारी किए निर्देश

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण अवैध प्लाटिंग की जानकारी वेबसाइट पर देगा– हिन्दुस्तान समाचार पत्र इस शीर्षक के साथ खबर में लिखता है– समीक्षा बैठक में शहर के विकास को लेकर लिए बड़े फैसले, जीरो टॉलरेंस की नीति पर होगा काम।

कोटद्वार में हंगामा करने वालो को पुलिस भेज रही नोटिस– अमर उजाला इस शीर्षक के साथ खबर में लिखता है– खंगाले जा रहे सीसीटीवी , थाने में बुलाकर हो रही पूछताछ।